व्यावसायिक संस्थाओं को बढ़ावा देना

2334. श्री मूल चन्द डागा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 1980 के सन्डे स्टेण्डर्ड में 'डिप्लोमा और डिग्रीज" शीर्षक से छपे संपादकीय की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या सरकार व्यवसायिक संस्थानों को बढ़ावा देगी और यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आज तक व्यवसायिक संस्थानों पर कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख). 2 नवम्बर, 1980 के "सन्डे स्टेन्डर्ड" में "डिप्लोमाज और डिग्रीज" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित संपादकीय लेख भारत सरकार के ध्यान में आया है ।

बम्बई स्थित विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान्, ने राज्य सरकार से प्रस्ताव किया है कि शैक्षिक वर्ष 1981–82 से संस्थान में आरम्भ किए जाने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रम को बन्द कर दिया जाए । कुछ वर्ष पहले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने यह सिफारिश की थी कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने वाली डिग्री संस्थाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करना आगामी विकास के लिए लाभदायक नहीं होगा और इससे संस्थाएं अनुसंधान सहित स्नातकोत्तर क्रिया-कलापों के विकास पर अपने प्रयास केन्द्रित नहीं कर पाएंगी । देश की अधिकांश संस्थाओं ने इस पर अमल करना शुरु कर दिया है । संस्थान की यह प्रस्ताव अब महाराष्ट्र राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

2. चौथी पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद संस्थाओं को अनुमोदित सामान्य योजनागत योजनाओं के लिए कोई भी सीधी केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है । अनुमोदित सामान्य योजनागत योजनाओं से सम्बोधित स्वीकृत केन्द्रीय हिस्सा राज्य की योजनाओं के माध्यम से दिया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार का प्रयास है कि तकनीकी शिक्षा (डिप्लोमा स्तर तक) के सभी स्तरों पर विद्यमान सुविधाओं को मोटे तौर पर समेकित किया जाए और संस्थाओं को विशिष्ट चुने हुए क्षेत्रों में सुदृढ़ करके उन्हें विकसित किया जाए । इस तरह से स्तरों में सुधार किया जा रहा है । पोलिटेकनिक स्तर पर भी, चुनिन्दा संस्थाओं में, उदाहरण के तौर पर दृव्य श्रव्य कक्षों संसाधन उत्पादन केन्द्रों की स्थापना, पुस्तकालयों और प्रयोग-शालाओं इत्यादि के सुधार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, कोटि सुधार कार्यक्रमों के लिए सीधी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है । पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर के ऐसे कार्यक्रमों के लिए पालिटेकनिकों हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कुल राशि 153.72 लाख रु० हैं जो इस प्रकार है :

1977–78	34.00 लाख रुपये
1978–79	62.35 लाख रुपये
1979–80	57.37 लाख रुपये
कुल	—— 153.72, लाख रुपये

Report of committee on Central Sheep and Wool Research Institute, Avikanagar, Rajasthan

2835. SHRI B. D. SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a six-member Expert Committee has found serious irregularities and malpractices in the functioning of the Central Sheep and Wool Research Institute, Avikanagar, Rajasthan;

(b) if so, the salient features of the disclosure made by the Expert Committee; and

(c) the action proposed to be taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) to (c) Part-I of the Expert Committee's report in respect of the Central Sheep and Wool Research Institute, Avikanagar, has been received so far.

Findings of the report are under consideration of the Indian Council of Agricultural Research.

रतलाम में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

2836. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम में जहां केन्द्रीय सरकार और रेलवे के बहुत से कार्यालय हैं, केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Development of non-cement Building Material

2837. SHRI KRISHNA PRATAP SINGH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government have asked the Cement Corporation of India to develop non-cement building materials and cement mixtures which are cheaper and equally effective; and

(b) if so, the details in this respect and whether any such material has since been developed?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Spray on Coconut Trees in Kerala

2838. SHRI A. NEELALOHITHADASAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Government of Kerala has submitted any scheme on comprehensive spraying of coconut trees as well as removal and rehabilitation of diseased plants for the assistance from I.C.A.R. and Central Government;

(b) if so, the details of the scheme;

(c) the action taken by the Central Government on it; and

(d) the action, the Central Government propose to take further?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Kerala has requested central assistance in support of the following two schemes which they have sanctioned and implemented:

(i) Scheme for spraying coconut palms to control leaf rot disease.

(ii) Comprehensive Coconut Development Programme.

For the first scheme they have sanctioned an amount of Rs. 167.50 lakhs for 1980-81 as against an estimated expenditure of Rs. 645.45 lakhs. The difference of the amounts is to be recovered from the coconut growers. This programme envisages two rounds of